

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
पौड़ी।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून:दिनांक: 10 सितम्बर, 2009

विषय:-केन्द्रीय विद्यालय पौड़ी, हेतु 2.061 है० भूमि निःशुल्क पट्टे पर हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2177 / 27ए०जे०ए०(2007-08), दिनांक-26.05.08 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-258 / 16(1) / 73-रा-1 दिनांक-09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-1695 / 97-1-1(60) / 93-रा-1 दिनांक-12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों को शिथिल करते हुए एवं राजस्व अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-28 / 18(2) / 09 दिनांक-06.01.09 के अनुसार कुल 2.061 है० भूमि जो ग्राम कोठार, पट्टी इडवालस्यूं तहसील एवं जिला पौड़ी के अन्तर्गत है एवं वर्तमान में नोन जैड०ए० श्रेणी-4 की है, को केन्द्रीय विद्यालय पौड़ी गढ़वाल, की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार नई दिल्ली को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर निःशुल्क आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- (1) यदि प्रश्नगत भूमि वन भूमि नहीं है तो केन्द्रीय विद्यालय संगठन को उक्त भूमि निःशुल्क हस्तांतरित कर दिया जाये, किन्तु यदि वन भूमि है तो निर्माण कार्य कराने से पहले भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम के अधीन केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्राप्त की जायेगी।
- (2) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।
- (3) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (4) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150 / 1 / 85(24)-रा-6 दिनांक-09अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा।

- (5) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
- (6) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।
- (7) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दुसंख्या-1 से 6 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2- उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)  
अपर सचिव।

पू0प0सं0- 850 /संमदिनांकित/ 2009

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन देहरादून।
4. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)  
अनु सचिव।